NEWSLETTER

शनिवार, 19 अगस्त 2023 | वॉल्यूम - 59

Interview | Cotton Weekly Physical chart | Share Market Update | Important News

बीआईएस कानून वापसी की मांग नहीं स्वीकार की तो , कॉटन जिनिंग फैक्ट्री को बंद कर देंगे

GOLD : 58378
SILVER : 70246
CRUDE OIL : 6737

राजस्थान में स्थित श्री गंगानगर क्षेत्र के जाने माने कॉटन जिनर आदित्य चितलांगिया बातचीत का सारांश

आदित्य चितलांगिया (अध्यक्ष),

अपर राजस्थान कॉटन एसोसिएशन, चितलंगिया कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री, श्री गंगानगर, राजस्थान

उन्होंने बताया की उनकी प्रथम जिनिंग फैक्ट्री की स्थापना 1979 में उनके दादाजी ने की थी। वर्तमान में उनके बड़े भाई श्री विक्रम चितलांगिया जी के दिशानिर्देश में तीन जिनिंग फैक्ट्री का संचालन कर रहे है। आदित्य जी अपर राजस्थान कॉटन एसोसिएशन में अध्यक्ष के पद की भूमिका भी निभा रहे है।

कॉटन इंडस्ट्रीज की वर्तमान स्थिति बताते हुए कहा की BIS के कानून की घोषणा से जिनर्स की समस्या बढ़ गई है। जिनर्स कैसे काम करे वह समझ नहीं पा रहा है। सरकार को BIS का कानून किसी भी कृषि उत्पाद पर लागू नहीं करना चाहिए। कॉटन एक नेचुरल फाइबर है। कॉटन कुदरती उत्पाद होने से इसकी ग्रेडिंग तो किसी स्तर पर संभव है लेकिन इसको कोई एक मापदंड में बांधना उचित नहीं है केवल मशीन निर्मित वस्तु में एक ही मापदंड पर निर्माण संभव है।

"आप कल्पना करे क्या किसान के बगीचे के सारे आम एक ही मिठास, एक ही रंग ओर एक जैसी गुठली के हो सकते है?" क्या सभी वृक्ष एक समान टहनी के हो सकते है, सरकार को ये समझना होगा की ये असंभव है। BIS कानून की सररंचना उपभोगता को निम्न स्तर के वस्तु के विक्रय से होने वाले नुकसान से बचाने की मंशा से की है जब की 99.99 % रुई की गाठ का व्यापार जिनिंग प्रोसेसिंग एवं धागा मिल के मध्य होती है, जहा पर धागा मिल के पास गुणवता मापने की लैब है जब की जिनिंग प्रोसेसिंग एकाइयों के पास लैब तक नहीं है। जिनिंग वाले तो मिल की लैब के आधार पर ही भुगतान प्राप्त करता है| एसी स्थिति में उपभोगता कानून विक्रेय करने वाले पर लगाने का कोई उचित आधार नहीं है।

इस वक्त हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कॉटन जिनिंग की 500 इकाइयां हैं और ये सभी सालभर में 60 लाख गांठ या यूं कहें कि 3 करोड़ क्विंटल कपास की प्रोसेसिंग करती हैं।

सरकार अपने फैसले को वापिस नहीं लेती है 1 नवम्बर 2023 से नार्थ झोन की सभी जिनिंग फ़ैक्टरिया हड़ताल पर रहेंगी जिसके कारण इन सभी फैक्ट्रियों से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे और देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। किसान, मजदूर, व्यापारी सब इस फैसले से प्रभावित होंगे।

16 अगस्त, 2023 को नार्थ एसोसिएशन में जिनर्स की मीटिंग के दौरान ये भी तय किया गया है अगर इस नियम की पुन:समीक्षा नहीं की गई तो,1 नवम्बर, 2023 से नार्थ की सारी जिनिंग फैक्ट्री को बंद रहेगी। अगर ऐसा होता है तो, कॉटन इंडस्ट्रीज की हर श्रृंखला पर इसका असर देखने को मिलेगा। पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है।

BIS का कानून 28 अगस्त, 2023 को लागु होने वाला था , जो अब 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। पर अभी भी, जिनर्स को जिनिंग फैक्ट्री चालू करे या नहीं वो समझ नहीं पा रहे है। जिनिंग ईकाइया भी सरकार के साथ कपास की गुणवता सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। और सरकार के साथ इस विषय पर सार्थक पहल की इच्छुक है| इस पर और अधिक चिंतन ओर विवेचना की जानी चाहिए की कही कठोर नियम से उद्योग चला पाना ही असंभव ना हो जाए |

आशा है की उपरोक्त कारणों पर सरकार सकारात्मक विचार करने के बाद ही निर्णय लेगी।

Download Our App "SIS CONNECT" For Daily Updates. CLICK HERE

FOR MORE INFORMATION
CONTACT - +91 - 91119 77771

कॉटन मार्केट की साप्ताहिक हलचल पर एक नजर

SMART INFO SERVICES

CALL : 91119 77771 - 5

WEEKLY CHART 19.08.2023

ICE COTTON			
MONTH	11:08:23	18:08:23	WEEKLY CHANGE
DEC	87.89	83.62	-4.27
MARCH	87.67	83.55	-4.12
MAY	87.54	83.68	-3.86
MCX (COTTON)			
AUG	60500	59980	-520
NCDEX (KAPAS)			
APRIL	1570	1576	6
NCDEX (COCUD KHAL)			
AUG	2627	2675	48
SEP	2660	2720	60
DEC	2550	2546	-4
SMART INFO SERVICE		CALL : 91119 77775	
CURRENCY ($)			
INDIAN (Rupee)	82.85	83.10	0.25
PAK (Pakistani Rupee)	285.825	296.991	11.166
CNY (Chinese yuan)	7.18935	7.28230	0.09295
BRAZIL (Real)	4.90088	4.97030	0.06942
AUSTRALIAN Dollar	1.52091	1.56790	0.04699
MALAYSIAN RINGGITS	4.559	4.65177	0.09277
COTLOOK "A" INDEX	96.70	94.10	-2.6
BRAZIL COTTON INDEX	82.29	81.75	-0.54
USDA SPOT RATE	84.00	79.14	-4.86
MCX SPOT RATE	60420	60960	540
KCA SPOT RATE (PAKISTAN)	17800	18200	400
GOLD ($)	1945.85	1918.40	-27.45
SILVER ($)	22.745	22.795	0.05
CRUDE ($)	83.04	81.40	-1.64

अगस्त माह के तीसरे सप्ताह में कॉटन के इंटरनेशल मार्केट मिला जुला रहा । इंटरनेशनल कॉटन एक्सचेंज के दिसंबर 23, मार्च 24 और मई 24 माह के लिए कॉटन के भाव क्रमशः -4.27, -4.12 और -3.86 सेंट तक कम हुवा ।

भारतीय बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कॉटन के दाम में कमी देखी गई। अगस्त माह के सौदा भाव में -520 रूपए प्रति कैंडी घट कर 59,980 रुपए पहुंचे।

एनसीडीइएक्स पर कपास के भाव इस बार 6 रूपए प्रति 20 किलो तक की बढ़ोतरी देखी गई वही खल के भाव में अगस्त, और सितम्बर माह के लिए क्रमशः 48 और 60 रूपए प्रति क्विंटल की बढ़त हुई। वही दिसंबर में 4 रुपए की गिरावट देखि गई।

अन्य देशों के एक्सचेंज मार्केट पर नजर करें तो कॉटलुक "ए" इंडेक्स पर -2.6 अंक की कमी आई है , ब्राजील कॉटन इंडेक्स पर -0.54 और यूएसडीए स्पॉट रेट पर -4.86 अंक तक कम हुवा है वही एमसीएक्स स्पॉट रेट पर 540 अंक की बढ़त दर्ज की गई है। पाकिस्तान के केसीए स्पॉट रेट पर सप्ताह अंत तक 400 रुपए तक भाव बढ़े।

शेयर मार्केट निवेशकों के लिए मिला-जुला रहा यह सप्ताह

14 अगस्त से 18 अगस्त 2023 के मध्य प्रमुख टेक्सटाइल कंपनीज की शेयर वेल्यू पर आधारित खबर

कंपनी	करंट प्राइस	हाई प्राइस	लोएस्ट प्राइस	हलचल
वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड	365.45	373.15	333.5	4.43%
अरविद लिमिटेड	155.7	161.6	138	8.28%
वेलसपन इंडिया	114.5	117.65	112.8	-2.18%
नितिन स्पिनर्स	244.15	249.30	233.50	1.73%
रेमण्ड	1946.95	2004.95	1883.9	-2.89%
अक्षिता कॉटन	26.13	26.75	26	-0.27%

50
Golden Jubilee Year

Maharashtra Cotton Conference 2023

Celebrating 50 years of excellence - The Jubliee celebration

"Empowering India's Cotton Industry for Inclusive Growth Because That's What We Deserve."

on

9th, 10th September 2023

The Grand Jalsa, NH 6, Ridhora Road,
Akola.

Don't miss the opportunity

Organized by
The Maharashtra Cotton Brokers Association, Akola

Registration fees: **₹5000/- + (18% GST)**

Soon Launching new Website and Payment Gateway

Email ID: mcbaconference2023@gmail.com

Supported by

Media Partner - Smart Info Services

बीआईएस कानून वापसी की मांग नहीं स्वीकार की तो , कॉटन जिनिंग फैक्ट्री को बंद कर देंगे

भारत सरकार द्वारा कपास गांठें बनाने, प्रसंस्करण और व्यापार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणिक करवाने का कानून बनाने के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान कीकॉटन जिनिंग एसोसिएशन विरोध में उतर आये हैं। हिसार में आज तीनों राज्यों के 100 से अधिक जिनर्स एकत्रित हुए और सरकार के इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठायी। जिनर्स की बैठक में सर्वसम्मत्ति से फैसला लिया गया कि सरकार के इस काले कानून को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जायेगा। सरकार यदि इस कानून को लागू करने से पीछे नहीं हटी तो सभी जिनर्स अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे और किसानों से कपास भी नहीं खरीदेंगे।

बैठक का आयोजन हरियाणा कॉटन जिनिंग एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा कॉटन जिनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील मित्तल ने कहा कि सरकार न जाने क्यों किसान, व्यापारी व उद्योगपतियों के खिलाफ काम कर रही है। भारतीय मानक ब्यूरो का नियम कॉटन प्रोसेसिंग व गांठें बनाने पर लागू करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

बीआईएस के नियम फैक्ट्री में निर्मित उत्पादों पर लागू होते हैं। कपास तो एक कृषि उत्पादन है और ये रॉ मैटीरियल है। कॉटन जिनर्स अपनी फैक्ट्री में सिर्फ कपास की प्रोसेसिंग करके आगे कपास को बेचते हैं, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में बीआईएस नियम लागू नहीं होने चाहिए। सरकार इसे पहले 27 अगस्त से ही लागू करना चाहती थी लेकिन अब सरकार इस कानून को 27 नवम्बर से लागू करने की बात कर रही है। जिनर्स के विरोध के चलते ही इस कानून को लागू करने का फैसला तीन महीने के लिए लंबित कर दिया गया है। मगर, पूरे देश के जिनर्स इस कानून को रद्द करवाना चाहते हैं और सरकार ने ये कानून रद्द नहीं किया तो जिनर्स अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे।

अपर राजस्थान कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अदित्य चितांगलिया ने इस मौके पर कहा कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में कहीं भी बीआईएस का नियम लागू नहीं होती है। ऐसे में केन्द्र सरकार ये कानून लागू करके गलत कर रही है। इस वक्त हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कॉटन जिनिंग की 500 इकाइयां हैं

और ये सभी सालभर में 60 लाख गांठों या यूं कहें कि 3 करोड़ क्विंटल कपास की प्रोसेसिंग करती हैं। सरकार अपने फैसले को वापिस नहीं लेती है तो इन सभी फैक्ट्रियों से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे और देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। किसान, मजदूर, व्यापारी सब इस फैसले से प्रभावित होंगे।

लोअर राजस्थान कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता ने कहा कि पूरी दुनिया में कहीं भी कॉटन प्रोसेसिंग या अन्य कृषि उत्पादन पर मानक ब्यूरो के नियम लागू नहीं हैं। ऐसे में देश को आगे बढ़ाने के बजाये सरकार पीछे धकेलने वाला काम क्यों कर रही है। सरकार यदि नियम लागू करना भी चाहती है तो इसे अनिवार्य करने के बजाये वैकल्पिक कर सकती है। मगर बीआईएस मानक पूरे नहीं करने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा रखकर सरकार जिनर्स को क्या अपराधी घोषित करना चाहती है।

पंजाब कॉटन फैक्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश बंसल ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट सेक्टर्स के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रही है। कॉटन उद्योगपति कॉटन प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं और जुर्म नहीं कर रहे। सरकार के इस गलत फैसले को एसोसिएशन किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दे सकती है क्योंकि सरकार जो चाहती है वो संभव ही नहीं है। सरकार नहीं मानी तो फैक्ट्रियां बंद करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा।

इस मीटिंग में हरियाणा कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के संरक्षक सुमेर चंद, कैशियर, श्यामसुंदर बधेरिया भूना, पंजाब से भगवान बंसल, अलवर से कुलदीप, हनुमानगढ़ से रविन्द्र, बलवंत खैरतल राजस्थान, आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

नार्थ कॉटन जिनिंग एसोसिएशन में लिया गया निर्णय, जैसा की श्री सुशिल मित्तल जी नव निर्वाचित अध्यक्ष जी ने बताया।

1. कोई भी जिनर सीसीआई टेंडर नहीं भरेगा।
2. नार्थ के जिनर्स 1 नवंबर 2023 से हड़ताल पर जाएंगे। कोई खरीद नहीं, कोई प्रसंस्करण नहीं और कोई बिक्री नहीं.

TOP 5 NEWS OF THE WEEK

भारत को अगस्त में रिकॉर्ड स्तर से कम बारिश का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रीष्मकालीन फसलों को खतरा।

मौसम विभाग के दो अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि भारत एक सदी से भी अधिक समय में अपने सबसे शुष्क अगस्त की ओर बढ़ रहा है, आंशिक रूप से अल नीनो मौसम पैटर्न के कारण बड़े क्षेत्रों में कम वर्षा होने की संभावना है।

वैश्विक कपास उत्पादन अगले सीजन में गिरावट की संभावना है

अगले सीजन में वैश्विक कपास उत्पादन में तीन प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है, जबकि खपत स्थिर रह सकती है और अंतिम स्टॉक कम हो सकता है। हालांकि, विश्लेषकों ने कहा है कि चीन कीमतों की कुंजी रखता है क्योंकि कम्युनिस्ट राष्ट्र की ओर से मांग में किसी भी तरह की गिरावट कीमतों में बढ़ोतरी को सीमित कर सकती है।

उत्तर भारत में कपास की फसल पर गुलाबी बॉलवर्म के हमले का खतरा मंडरा रहा है

उत्तर भारत में कपास की फसल पिंक बॉलवर्म (पीबीडब्ल्यू) के हमले के खतरे में है और पिछले दो वर्षों की तुलना में इस साल कीटों के हमले की तीव्रता अधिक देखी गई है। जबकि उत्तर में खरीफ 2022-23 के दौरान केवल सीजन के अंत में कपास में पीबीडब्ल्यू देखा गया था, इस साल यह कीट सीजन की शुरुआत में ही सामने आ गया है

सीएआई ने वित्त वर्ष 2023 में कपास की फसल का अनुमान 311.18 लाख गांठ बनाए रखा है

अक्टूबर 2022 से जुलाई 2023 के महीनों के लिए कुल कपास आपूर्ति 170 किलोग्राम की 332.30 लाख गांठ होने का अनुमान है। प्रत्येक (प्रत्येक 162 किलोग्राम की 348.71 लाख रनिंग गांठों के बराबर), जिसमें 170 किलोग्राम की 296.80 लाख गांठों की आवक शामिल है। प्रत्येक (162 किलोग्राम की 311.46 लाख रनिंग गांठों के बराबर), 170 किलोग्राम की 11.50 लाख गांठों का आयात।

तमिलनाडु राज्य ने शुल्क-मुक्त कपास आयात के लिए तत्काल कोटा की मांग की।

तमिलनाडु ने कोटा प्रणाली के तहत शुल्क मुक्त कपास आयात की वकालत की है। राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार से चालू गैर-आवक सीजन के लिए 20-25 लाख गांठ शुल्क मुक्त कपास आयात का कोटा जारी करने की मांग की है।

कॉटन फिजिकल मार्केट अगस्त माह के तीसरे सप्ताह में कॉटन के भाव में उतार चढ़ाव देखा गया।

यह सप्ताह कॉटन फिजिकल मार्केट के लिए मिला जुला रहा। नार्थ, सेंट्रल और साउथ तीनों ही झोन में कॉटन के भाव में भी काम ज्यादा देखने को मिला।

नार्थ झोन पंजाब और पंजाब में 50 रुपए प्रति मंड की कमी देखी गई वही हरयाणा में सबसे ज्यादा 100 रुपए प्रति मंड की तेजी देखी गई।

वही सेंट्रल झोन के गुजरात राज्य में 500 रूपए प्रति कैंडी की कमी देखने को मिली। जबकि महाराष्ट्र में 500 रुपए तक की तेजी हुई, मध्य प्रदेश में सबसे कम 300 रूपये की तेज़ी देखी गई।

साउथ झोन में भी मार्केट में बढ़त जारी रही। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 1,000 रूपए प्रति कैंडी तक की बढ़त देखी जबकि कर्नाटक में 200 रुपए बढ़ा। जबकि ओडिशा में रुपये 100 की कमी देखने को मिली।

SMART INFO SERVICES
india.smartinfo@gmail.com
Call : 91119 77775

DATE: 19.08.2023

WEEKLY COTTON BALES MARKET

STATE	STAPLE LENGTH	14.08.23		19.08.23		AVERAGE PRICE
		LOW	HIGH	LOW	HIGH	
NORTH ZONE						
PUNJAB	28.5	6,000	6,100	5,950	6,050	-50
HARYANA	27.5/28	5,900	6,000	5,975	6,100	100
UPER RAJASTHAN	28	6,150	6,300	6,150	6,300	0
CENTRAL ZONE						
GUJARAT	29	61,000	61,300	60,500	60,800	-500
MADHYA PRADESH	29	60,000	60,500	60,300	60,800	300
MAHARASHTRA	29 vid.	60,000	60,500	60,500	61,000	500
SMART INFO SERVICES CALL : 91119 77775						
SOUTH ZONE						
ODISHA	29.5	61,600	61,700	61,500	61,600	-100
KARNATAKA	29.5/30 mm	60,500	61,000	61,000	61,200	200
ANDHRA PRADESH	29.5/30 mm	60,500	61,000	61,500	62,000	1,000
TELANGANA	29.5/30 mm 78-80 RD	60,500	61,500	60,500	61,500	0

NOTE : There may be some changes in the rate depending on the quality.
Punjab, Haryana and Rajasthan rates in maund the rest in Candy

NEWSLETTER

Saturday, 19 August 2023 | Volume - 59

Interview | Cotton Weekly Physical chart | Share Market Update | Important News

If the demand for withdrawal of BIS law is not accepted, the cotton ginning factory will be closed

GOLD : 58378
SILVER : 70246
CRUDE OIL : 6737

Synopsis of the conversation with Aditya Chitlangia, a renowned cotton ginner from Sri Ganganagar region, Rajasthan.

Aditya Chitlangia (President),
Upper Rajasthan Cotton Association, Chitlangiya Cotton Ginning & Pressing Factory, Sri Ganganagar, Rajasthan

He told that his first ginning factory was established in 1979 by his grandfather. Presently, he is running three ginning factories under the guidance of his elder brother Mr. Vikram Chitlangia. Aditya ji is also playing the role of President in Upper Rajasthan Cotton Association.

Explaining the current situation of cotton industries, said that the problem of ginners has increased due to the announcement of BIS law. He is not able to understand how the ginners work. Government should not apply BIS law on any agricultural product. Cotton is a natural fiber. Cotton being a natural product, its grading is possible at some level, but it is not appropriate to tie it to any one parameter. Manufacturing is possible only on a single parameter in a machine-made item.

"Can you imagine if all the mangoes in a farmer's garden can be of the same sweetness, the same color and the same seed?" Can all trees be of the same branch, the government has to understand that this is impossible. The BIS Act is designed to protect the consumer from loss caused by the sale of substandard goods, when 99.99% of cotton bales are traded between ginning processing and yarn mills, where yarn mills have quality measuring facilities. There is a lab while the ginning processing units do not even have a lab. The ginner receives payment only on the basis of the lab of the mill. In such a situation, there is no proper basis for imposing consumer law on the seller.

At present there are 500 cotton ginning units in Haryana, Punjab and Rajasthan and all of them process 60 lakh bales or say 30 million quintals of cotton in a year.

The government does not take back its decision, from 1 November 2023, all the ginning factories of the North Zone will be on strike, due to which lakhs of people associated with all these factories will become unemployed and the country's economy will be badly affected. Farmers, laborers, businessmen all will be affected by this decision.

It has also been decided during the meeting of Ginners in North Association on August 16, 2023 that if this rule is not reviewed again, then from November 1, 2023, all the Ginning factories of North will remain closed. If this happens, its effect will be seen on every chain of cotton industries. The whole economy can deteriorate.

The BIS law was to come into effect on August 28, 2023, which has now been postponed for 3 months. But still, the ginners are not able to understand whether to start the ginning factory or not. Ginning units are also committed to improving the quality of cotton with the government. And is willing to take meaningful initiative on this subject with the government. More contemplation and discussion should be done on this so that it should not become impossible to run the industry due to strict rules.

It is expected that the government will take a decision only after considering the above reasons positively.

Download Our App "SIS CONNECT" For Daily Updates. CLICK HERE

FOR MORE INFORMATION
CONTACT - +91 - 91119 77771

A look at the weekly movement of the cotton market

SMART INFO SERVICES CALL : 91119 77771 - 5 WEEKLY CHART 19.08.2023			
ICE COTTON			
MONTH	11:08:23	18:08:23	WEEKLY CHANGE
DEC	87.89	83.62	-4.27
MARCH	87.67	83.55	-4.12
MAY	87.54	83.68	-3.86
MCX (COTTON)			
AUG	60500	59980	-520
NCDEX (KAPAS)			
APRIL	1570	1576	6
NCDEX (COCUD KHAL)			
AUG	2627	2675	48
SEP	2660	2720	60
DEC	2550	2546	-4
SMART INFO SERVICE		CALL : 91119 77775	
CURRENCY ($)			
INDIAN (Rupee)	82.85	83.10	0.25
PAK (Pakistani Rupee)	285.825	296.991	11.166
CNY (Chinese yuan)	7.18935	7.28230	0.09295
BRAZIL (Real)	4.90088	4.97030	0.06942
AUSTRALIAN Dollar	1.52091	1.56790	0.04699
MALAYSIAN RINGGITS	4.559	4.65177	0.09277
COTLOOK "A" INDEX	96.70	94.10	-2.6
BRAZIL COTTON INDEX	82.29	81.75	-0.54
USDA SPOT RATE	84.00	79.14	-4.86
MCX SPOT RATE	60420	60960	540
KCA SPOT RATE (PAKISTAN)	17800	18200	400
GOLD ($)	1945.85	1918.40	-27.45
SILVER ($)	22.745	22.795	0.05
CRUDE ($)	83.04	81.40	-1.64

The international cotton market was mixed in the third week of August. Cotton prices for the months of December 23, March 24 and May 24 on the International Cotton Exchange declined by -4.27, -4.12 and -3.86 cents respectively.

A decrease in the price of cotton was observed on the Multi Commodity Exchange (MCX) in the Indian market. In the month of August, the bargain price decreased by Rs.520 per candy to reach Rs.59,980.

Cotton prices on NCDEX have seen an increase of up to Rs.6 per 20 kg this time, while the prices of Khal have increased by Rs.48 and Rs.60 per quintal for the month of August and September respectively. The same saw a fall of Rs 4 in December.

Looking at the exchange market of other countries, there has been a decrease of -2.6 points on the Cotlook "A" index, -0.54 points on the Brazil Cotton Index and -4.86 points on the USDA spot rate, while the MCX spot rate has gained 540 points. has been registered. At the KCA spot rate of Pakistan, the price increased up to Rs 400 by the end of the week.

It was a mixed week for stock market investors

News based on share value of major textile companies from 14th August to 18th August 2023

COMPANY	CURRENT PRICE	HIGH PRICE	LOW PRICE	MOVEMENT
VARDHMAN TEXTILE LIMITED	365.45	373.15	333.5	4.43%
ARVIND LIMITED	155.7	161.6	138	8.28%
WELSPUN INDIA	114.5	117.65	112.8	-2.18%
NITIN SPINNERS	244.15	249.30	233.50	1.73%
RAYMOND	1946.95	2004.95	1883.9	-2.89%
AXITA COTTON	26.13	26.75	26	-0.27%

If the demand for withdrawal of BIS law is not accepted, the cotton ginning factory will be closed

Cotton Ginning Associations of Haryana, Punjab and Rajasthan have come out in protest against the Government of India's law to get certified by the Bureau of Indian Standards for making, processing and trading cotton bales. More than 100 ginners from all the three states gathered in Hisar today and raised their voice against this law of the government. In the meeting of Ginners, it was unanimously decided that this black law of the government will not be allowed to be implemented under any circumstances. If the government does not step back from implementing this law, then all the ginners will shut down their factories and will not even buy cotton from the farmers.

The meeting was organized by the Haryana Cotton Ginning Association.
Talking to reporters after a meeting held at a private restaurant, Haryana Cotton Ginning Association President Sushil Mittal said that the government is working against farmers, traders and industrialists. There is no justification for applying the rules of the Bureau of Indian Standards on cotton processing and bale making.

BIS norms are applicable to the products manufactured in the factory. Cotton is an agricultural product and it is a raw material. Cotton ginners only process cotton in their factory and sell cotton further, so BIS rules should not be applicable in this whole process. Earlier, the government wanted to implement it from 27th August itself, but now the government is talking about implementing this law from 27th November. The decision to implement this law has been postponed for three months due to the opposition of the ginners. But, the ginners of the whole country want this law to be repealed and if the government does not repeal this law, the ginners will shut down their factories.

Aditya Chitangalia, President of Upper Rajasthan Cotton Association, said on the occasion that BIS rule is not applicable anywhere in the business to business model. In such a situation, the central government is doing wrong by implementing this law. At present there are 500 cotton ginning units in Haryana, Punjab and Rajasthan and all of them process 60 lakh bales or say 30 million quintals of cotton in a year.

If the government does not withdraw its decision, lakhs of people associated with all these factories will become unemployed and the country's economy will be badly affected. Farmers, laborers, businessmen all will be affected by this decision.

Kuldeep Gupta, president of the Lower Rajasthan Cotton Association, said that anywhere in the world, Bureau of Standards regulations are not applicable to cotton processing or other agricultural production. In such a situation, instead of taking the country forward, why is the government doing the work of pushing back. If the government also wants to implement the rule, it can make it optional instead of making it mandatory. But what does the government want to declare the ginners as criminals by imposing heavy fines and jail term for not meeting the BIS standards.

Suresh Bansal, president of the Punjab Cotton Factories Association, said that the government was acting like a puppet in the hands of the corporate sectors. The cotton industrialists are doing the work of cotton processing and are not committing crimes. The association cannot allow this wrong decision of the government to be implemented at any cost because what the government wants is not possible. If the government does not agree, they will be left with no option but to shut down the factories.

Patron of Haryana Cotton Ginners Association Sumer Chand, Cashier, Shyamsundar Badheria Bhuna, Bhagwan Bansal from Punjab, Kuldeep from Alwar, Ravindra from Hanumangarh, Balwant Khairtal Rajasthan, etc. were mainly present in this meeting.

The decision taken in the North Cotton Ginning Association, as told by Mr. Sushil Mittal, the newly elected President.

1. No generator will fill CCI tender.

2. All Indian ginners will go on strike from 1st November 2023. No buying, no processing and no selling.

TOP 5 NEWS OF THE WEEK

India is facing record low rainfall in August, threatening summer crops.

India is headed for its driest August in more than a century, partly due to the El Nino weather pattern that is likely to bring deficient rainfall over large areas, two meteorological officials said on Friday.

Global cotton production likely to decline next season.

Global cotton production is expected to decline by three percent next season, while consumption may remain stable and ending stocks may be low. However, analysts said China holds the key to prices as any drop in demand from the communist nation could limit further upside.

The cotton crop in North India is facing the threat of pink bollworm attack.

Cotton crop in North India is under threat of Pink Bollworm (PBW) attack and the intensity of pest attack has been observed more this year as compared to last two years. While PBW in cotton was seen only at the end of the season during Kharif 2022-23 in the north, this year the pest has appeared early in the season.

CAI maintains cotton crop estimate of 311.18 lakh bales in FY2023

The total cotton supply for the months of October 2022 to July 2023 is estimated at 332.30 lakh bales of 170 kg each. each (equivalent to 348.71 lakh running bales of 162 kg each), including arrivals of 296.80 lakh bales of 170 kg each. Import of 11.50 lakh bales of 170 kg each (equivalent to 311.46 lakh running bales of 162 kg).

The state of Tamil Nadu demanded an immediate quota for duty-free cotton imports.

Tamil Nadu has advocated duty free cotton import under quota system. State Chief Minister MK Stalin has demanded the central government to release a quota of 20-25 lakh bales of duty free cotton import for the current non-incoming season.

Cotton Physical Market In the third week of August, cotton prices saw ups and downs..

It was a mixed week for the cotton physical market. In all the three zones North, Central and South, there was more work in the price of cotton.

North Zone Punjab and Punjab saw a decrease of Rs 50 per mand, while Haryana saw the maximum increase of Rs 100 per mand.

In the Gujarat state of the Central Zone, a shortage of Rs.500 per candy was seen. While Maharashtra saw a rise of up to Rs 500, Madhya Pradesh saw the lowest rise of Rs 300.

The market continued to grow in the South Zone as well. Andhra Pradesh saw the maximum increase of up to Rs 1,000 per candy while Karnataka saw an increase of Rs 200. While Odisha saw a shortfall of Rs 100.

SMART INFO SERVICES
india.smartinfo@gmail.com
Call : 91119 77775

DATE: 19.08.2023

WEEKLY COTTON BALES MARKET

STATE	STAPLE LENGTH	14.08.23		19.08.23		AVERAGE PRICE
		LOW	HIGH	LOW	HIGH	
NORTH ZONE						
PUNJAB	28.5	6,000	6,100	5,950	6,050	-50
HARYANA	27.5/28	5,900	6,000	5,975	6,100	100
UPER RAJASTHAN	28	6,150	6,300	6,150	6,300	0
CENTRAL ZONE						
GUJARAT	29	61,000	61,300	60,500	60,800	-500
MADHYA PRADESH	29	60,000	60,500	60,300	60,800	300
MAHARASHTRA	29 vid.	60,000	60,500	60,500	61,000	500
SMART INFO SERVICES CALL : 91119 77775						
SOUTH ZONE						
ODISHA	29.5	61,600	61,700	61,500	61,600	-100
KARNATAKA	29.5/30 mm	60,500	61,000	61,000	61,200	200
ANDHRA PRADESH	29.5/30 mm	60,500	61,000	61,500	62,000	1,000
TELANGANA	29.5/30 mm 78-80 RD	60,500	61,500	60,500	61,500	0

NOTE : There may be some changes in the rate depending on the quality.
Punjab, Haryana and Rajasthan rates in maund the rest in Candy